

यूजीसी और एआईसीटीई की जगह लेगी नई एजेंसी

यूपीए सरकार के समय भी हुआ था बदलाव का प्रयास

नवज्योति, जयपुर

शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार हर



दिन नए बदलाव कर रही है। अब बारी उच्च शिक्षा की है। देश के शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार होने जा रहे हैं। केन्द्र सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) को समाप्त कर उनकी जगह एक हायर एजुकेशन रेग्युलेटर बनाने जा रही है। इस रेग्युलेटर का नाम अभी हायर एजुकेशन एंपावरमेंट रेग्युलेशन एजेंसी (एचईईआरए) रखा गया है।

तेजी से किया जा रहा है काम

नए रेग्युलेटर को बनाने में समय लग सकता है और इसे देखते हुए सुधार के अस्थायी उपाय के तौर पर मौजूदा नियमों में संशोधन करने पर विचार किया जाएगा। एक्सपर्ट्स लंबे समय से इस बड़े बदलाव की जरूरत बता रहे थे, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई खास प्रगति नहीं हुई थी। मार्च में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया। सूत्रों

के अनुसार कानून को तैयार करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। मानव संसाधन मंत्रालय और नीति आयोग नए कानून पर काम कर रहे हैं।

अब तक का सबसे बड़ा सुधार

यूजीसी और एआईसीटीई की जगह एक सिंगल रेग्युलेटर लाना अब तक का सबसे बड़ा सुधार होगा और इससे अधिकार क्षेत्र से जुड़ी सभी कमियां दूर हो जाएंगी और इसके साथ ही ऐसे रेग्युलेटरी प्रोविजंस भी समाप्त होंगे जिनकी अब जरूरत नहीं है। हायर एजुकेशन में कई रेग्युलेटरी अथॉरिटीज की जगह एक रेग्युलेटर लाने का विचार नया नहीं है। यूपीए की पिछली सरकार में यशपाल कमिटी और नेशनल नॉलेज कमिशन के अलावा मौजूदा सरकार की ओर से बनाई गई हरि गौतम कमेटी ने भी इसकी सिफारिश की थी।

इंस्पेक्टर राज होगा समाप्त

टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल एजुकेशन को अलग करने का चलन अब पुराना हो गया है। एक रेग्युलेटर होने से इंस्टिट्यूशंस के बीच तालमेल बेहतर होगा। एजेंसी बनाने का मकसद इंस्पेक्टर राज और उत्पीड़न को समाप्त करना है, जिससे यूजीसी को जोड़कर देखा जाता है। लेकिन नए रेग्युलेटर को भी जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाने की शक्ति दी जाएगी।